[2008] 2 एस.सी.आर. 604

भारतीय संघ एवं अन्य

बनाम

एस. कृष्णन एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 1103/2008)

8 फरवरी, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और एस.एच. कपाड़िया, जे. जे.]

सेवा कानून: समाप्ति - कर्मचारी की नियुक्ति अनुसूचित जनजाति-मलयाली समुदाय का सदस्य होने का दावा करने वाले कर्मचारी की नियुक्ति-- समापन, गलत सामुदायिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए - इसके बाद कल्याण निदेशक के पत्र पर भरोसा करते हुए कर्मचारी का मामला यह आया कि वह लंबाडी समुदाय, एक अनुसूचित जनजाति का था-- उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया और समाप्ति आदेश को रद्द कर दिया गया - की स्थिरता - अभिनिर्धारित : चूँकि कर्मचारी ने अनुसूचित जनजाति, मलयाली समुदाय के सदस्य के रूप में आवेदन किया था और उसे अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित पद के संबंध में नियुक्त किया गया था इसलिए यह टिकाऊ नहीं है। समुदाय प्रमाण पत्र गलत था - इससे भी अधिक, लंबाडी अनुसूचित जनजाति का हिस्सा नहीं था - उच्च न्यायालय ने पत्र पर गलत भरोसा किया क्योंकि यह सिफ़ारिश की प्रकृति का था और संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में किसी भी प्रविष्टि से संबंधित नहीं था।

प्रतिवादी की नियुक्ति रेलवे विभाग में हुई थी। उन्होंने अनुसूचित जनजाति, मलयाली समुदाय का सदस्य होने का दावा किया। गलत सामुदायिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के कारण उन्हें सेवा से हटा दिया गया था। इस बीच, प्रतिवादी ने यह घोषणा करने के लिए एक आवेदन दायर किया कि वह मलयाली समुदाय से है। प्रतिवादी ने बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी और अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया गया। इसके बाद प्रतिवादी ने इस आधार पर एक रिट याचिका दायर की कि वह हिंदू लम्बाडी जाति से है जो एक अनुसूचित जनजाति है। उच्च न्यायालय ने जिला कल्याण निदेशक के पत्र पर भरोसा करते हुए कहा कि लंबाडी तमिलनाडु राज्य में एक अनुसूचित जनजाति है और प्रतिवादी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और समाप्ति आदेश को रद्द कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए मानाः

1.1 प्रतिवादी के नियुक्ति आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी नियुक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित पद पर की गई है। प्रतिवादी की इस दलील के संबंध में कि उसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में नियुक्त किया गया था, न की अनुसूचित जनजाति के के सदस्य के रूप में। यदि वास्तव में प्रतिवादी को सामान्य श्रेणी के पद के संबंध में नियुक्त किया गया था, तो सामुदायिक प्रमाणपत्र दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, यह घोषणा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी कि वह मलयाली समुदाय से है।

प्रस्तुत रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने मलयाली समुदाय का सदस्य होने

का दावा करते हुए अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में आवेदन किया था। सामुदायिक प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया। मूलतः यही बात का अंत है। उनका आगे का रुख यह है कि भले ही वह मलयाली समुदाय का नहीं है, लेकिन वह लंबाडी समुदाय से है, इसका वास्तव में कोई महत्व नहीं है। राज्य के विद्वान वकील द्वारा अनुसूचित जाति आैर अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित समुदाय का विवरण देने वाला दस्तावेज स्पष्ट रूप से प्रतिवादी के दावे को गलत साबित करता है कि लंबाडी समुदाय अनुसूचित जाति का हिस्सा था। दस्तावेज़ संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के तहत जारी किया गया था। जैसा कि बाद में संशोधित किया गया। [पैरा 7] [608-एफ, जी; 609-ए, 8, सी]

1.2 संविधान आदेश में की गई प्रविष्टि में जोड़ने या हटाने के माध्यम से कोई परिवर्तन करने की कोई गुजांइश नहीं है। उच्च न्यायालय ने कल्याण निदेशक कार्यालय के पत्र पर भरोसा करके स्पष्ट रूप से खुद को गलत दिशा में निर्देशित किया। इस पर नंगी दृष्टि डालने से पता चलता है कि वह वास्तव में संविधान (अनुसूचित जाति आैर अनुसूचित जनजाति) आदेश में किसी भी प्रविष्टि से सम्बन्धित नहीं था, अधिक से अधिक एक सिफारिश की प्रकृति में था। इस प्रकार उच्च न्यायालय का आदेश टिकाऊ नहीं है आर इसे रद्द किया जाता है। [पैरा 8 और 9] [609-डी, ई, एफ]

"पालघाट जिला तंदन समुध्या सर्रिथि और अन्य, 1994 एससीसी 359; महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद और अन्य 2000 (5) सप्ल. एससीआर 651 - पर निर्भर।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1103/2008

रिट याचिका संख्या 24911/2001 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय आर आदेश दिनांक 17.08.2005 से।

अपीलकर्ताओं के लिए अशोक भान, टी.ए. खान, बी.के. प्रसाद, डी.एस. मेहरा

प्रत्यर्थीगण के लिए ए.के. गांगुली, आर. सुदारवर्धन, पी.आर. कोविलन पूंगकुंट्रान, नरेश कुमार, एस. जोसेफ अरित्सटोटल, एस. प्रभु रामासुब्रमण्यम और वी.जी. प्रगासम।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. इस अपील में चुनौती मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले को दी गई है, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चेन्नई (संक्षेप में, 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका को अनुमति दी गई है।

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि: रेलवे विभाग द्वारा वर्ष 1976 में प्रतिवादी को गैंगमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रतिवादी द्वारा अनुसूचित जनजाति यानी मलयाली समुदाय का सदस्य होने का दावा किया। सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उसे सामुदायिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। नायब तहसीलदार, धर्मपुरी ने 16.8.1976 को एक प्रमाण पत्र जारी किया। वर्ष 1991 में दक्षिण रेलवे, धर्मपुरी के महाप्रबंधक ने जिला कलेक्टर से अनुरोध किया कि प्रतिवादी के सामुदायिक प्रमाण पत्र को सत्यापित करवाया जावे। जिला कलेक्टर ने एक रिपोर्ट भेजी जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी प्रस्तुत सामुदायिक प्रमाण पत्र फर्जी था और उसे रद्द कर दिया गया।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच अमल में लाई गई।

विभागीय जांच के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी ने यह घोषणा करने के लिए कि वह मलयाली समुदाय से है, जिला मुंसिफ कोर्ट, धर्मपुरी में एक सिविल मुकदमा यानी ओएस नंबर 4/1998 दायर किया। उक्त मुकदमे में मूल सामुदायिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। जांच अधिकारी ने अपनी जाँच पूर्ण कर अपनी रिपोर्ट में सेवा से हटाने का आधार दिनांक 23.12.1998 के आदेश को माना गया। मूल आवेदन अर्थात O.A.No.1156/1999 दायर करके उक्त आदेश को चुनौती दी गई थी। उसका निस्तारण इस टिप्पणी के साथ किया गया कि यदि कोई विभागीय अपील की जाती है तो उसे एक निश्चित समय के भीतर निपटाया जाएगा। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील खारिज किये जाने के बाद एक नई पुनरीक्षण दायर की गई। चूँकि, प्रतिवादी के अनुसार, पुनरीक्षण याचिका के निस्तारण में कुछ देरी हुई थी, इसलिये प्रकरण O.A.No.832/2000 ट्रिब्यूनल को स्थानांतरित कर दिया गया। दिनांक 28.07.2000 के आदेश द्वारा ट्रिब्यूनल ने पुनरीक्षण प्राधिकरण को एक विशेष समय के भीतर आदेश पारित करने का निर्देश दिया। पुनरीक्षण प्राधिकरण ने 23.12.1998 से सेवा से हटाने के आदेश को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में से एक में संशोधित किया। एक अन्य मूल आवेदन, यानि O.A.No 1403/2000, ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर किया गया था, जिसे खारिज किया गया था।

4. रिट याचिका में प्रतिवादी का रुख यह था कि यद्यपि विवाद यह था कि क्या वह अनुसूचित जनजाति, यानी मलयाली समुदाय से था, वास्तव में, वह हिंदू लम्बाडी जाति से था जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है। कुछ संचारों पर भरोसा किया

गया, विशेष रूप से, कल्याण अधिकारी कार्यालय, वैल्लोर के पत्र दिनांक 3.2.1971 पर जिसमें यह स्वीकार किया गया कि कन्याकुमारी जिले और एक अन्य तालुक को छोड़कर पूरे राज्य में लम्बाडी (सुगालिस) को अनुसूचित जनजाति माना जाता था। अपीलकर्ताओं, भारत संघ और तमिलनाडु राज्य ने रिट याचिका का विरोध करते हुए कहा कि लंबाडी समुदाय अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है। और, वास्तव में, प्रतिवादी ने अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित पद के संबंध में रोजगार प्राप्त किया है, वह यह दलील नहीं दे सकता कि वह लंबाडी समुदाय से है, जो उसके पहले के दावे से भिन्न है।

5. उच्च न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित जिला कल्याण निदेशक के पत्र पर भरोसा करते हुए यह माना कि प्रतिवादी अनुसूचित जनजाति का था और इसलिए, विभागीय अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस अपील की सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने यह रुख अपनाया कि प्रतिवादी को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में नियुक्त किया गया था, न कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में और इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अनुसूचित जनजाति का है या नहीं।

6. भारत संघ और तमिलनाडु राज्य के विद्वान वकील का रुख यह है कि लंबाडी तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं है। किसी भी स्थिति में, यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, जैसा कि प्रतिवादी ने तर्क दिया है कि उसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में नियुक्त किया गया था। तमिलनाडु राज्य के विद्वान वकील ने

समाज कल्याण विभाग के आदेश संख्या 1773, दिनांक 23.6.1994 को दायर किया है जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित समुदायों का विवरण दिया। उसी के संदर्भ में, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि लम्बाडी अनुसूचित जाति नहीं है।

7. इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, प्रतिवादी के मूल सेवा रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए। नियुक्ति आदेश से प्रतीत होता है कि उनकी नियुक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित पद पर की गयी है। यदि वास्तव में प्रतिवादी को सामान्य श्रेणी के पद पर नियुक्त किया गया था, तो सामुदायिक प्रमाणपत्र दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा यह घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि वह मलयाली समुदाय से है। प्रस्तुत रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने मलयाली समुदाय का सदस्य होने का दावा करते हुए अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में आवेदन किया था। प्रस्तुत सामुदायिक प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया। मूलतः यही मामले का अंत है। उनका आगे का रुख यह है कि भले ही वह मलयाली समुदाय से नहीं हैं, लेकिन वह लंबाडी समुदाय से हैं, इसका वास्तव में कोई मतलब नहीं है। फिर भी, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि विद्वान वकील द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित समुदायों का विवरण देने वाला संदर्भित दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से प्रतिवादी के दावे को गलत साबित करता है कि लंबाडी समुदाय अनुसूचित जनजाति का हिस्सा था। तमिलनाडु राज्य के विद्वान वकील द्वारा जिस दस्तावेज का उल्लेख किया गया है, वह संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950

(संक्षेप में, 'संविधान आदेश') के तहत जारी किया गया था, जैसा कि बाद में संशोधित किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि लंबाडी अनुसूचित जनजाति का हिस्सा नहीं था।

8. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा गया है पालघाट जिला थंडन सामुदायिक समिति एवं अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य (1994) एससीसी 359), और महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद और अन्य (2000) 5 (सप्ल) एससीआर 651), में कि संविधान आदेश में की गई प्रविष्टि में जोड़ने या हटाने के माध्यम से कोई परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उच्च न्यायालय ने कल्याण निदेशक कार्यालय के दिनांक 3.2.1971 के पत्र पर भरोसा करके स्पष्ट रूप से खुद को गलत दिशा में निर्देशित किया। इस पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि यह वास्तव में संविधान आदेश में किसी भी प्रविष्टि से संबंधित नहीं था, लेकिन अधिक से अधिक एक सिफारिश की प्रकृति में था जैसा कि तमिलनाडु राज्य के विद्वान वकील ने सही ढंग से तर्क दिया है।

9. किसी भी कोण से देखने पर उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं है और उसे खारिज किया जाता है।

10. लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील की अनुमति दी जाती है।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजन खत्री (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।